



- वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल दो हजार तेईस-चौबीस का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया—कहा आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर साढ़े छह से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
- भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने कार निकोबार से कैम्पबेल—बे हवाई अड्डे के लिए संचालन एवं रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वराज द्वीप में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया।



वित्तमंत्री सीतारामन आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार तेईस-चौबीस में वित्त वर्ष दो हजार चौबीस-पच्चीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर साढ़े छह से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष दो हजार तेईस-चौबीस में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार वस्तु और सेवाकर—जीएसटी और ऋण शोधन और दिवाला कानून—आईबीसी जैसे ढांचागत सुधार भी परिपक्व हो गये हैं और उनके वांछित परिणाम मिलने लगे हैं।

महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक वित्त वर्ष दो हजार पच्चीस में मुद्रास्फीति की मुख्य दर साढ़े चार प्रतिशत और वित्त वर्ष दो हजार छब्बीस में चार दशमलव एक प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए दो हजार चौबीस में मुद्रास्फीति चार दशमलव छह प्रतिशत और दो हजार पच्चीस में चार दशमलव दो प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष दो हजार चौबीस में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर वर्ष दो हजार बीस की तुलना में बीस प्रतिशत अधिक रही है। इस वर्ष भी वृद्धि दर सुदृढ़ रहने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी और बहुआयामी गरीबी में कमी और श्रम बल भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ विकास समावेशी रहा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की वास्तविक जीडीपी दर में वित्त वर्ष दो हजार चौबीस में आठ दशमलव दो प्रतिशत वृद्धि हुई है और लगातार तीसरे वर्ष ये सात प्रतिशत से अधिक दर्ज हुई है। सर्वेक्षण में दो हजार चौबीस के लिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य सकारात्मक बताया गया है, जिसमें वस्तु व्यापार बढ़ने की संभावना है।



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज आम बजट प्रस्तुत करेंगी। आकाशवाणी का पोर्ट ब्लेयर केन्द्र बजट का आंखो देखा हाल के अलावा बजट पूर्व और बजट के बाद होने वाले परिचर्चाओं का प्रसारण करेगा। आज सुबह नौ बजे से प्रसारण की व्यवस्था की गई है। दस बजकर दस मिनट से वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने का आंखो देखा हाल भी प्रसारित होगा। आज के कार्यक्रमों को देखते हुए आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से आज शाम सात बजकर पांच मिनट पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के समय में परिवर्तन किया गया है। अब आज शाम का प्रादेशिक समाचार सात बजकर पांच मिनट के स्थान पर शाम पांच बजे सुना जा सकेगा।



अंडमान निकोबार कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यभार संभालने पर रियर एडमिरल बिपलब होता ने उप-राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विभिन्न योजनाबद्ध परियोजनाओं पर चर्चा की गई।



अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने कल कार निकोबार से कैम्पबेल—बे हवाई अड्डे के लिए संचालन एवं रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर नागरिक उड्डयन सचिव विश्वेन्द्र और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक एन वी सुब्बारायडू ने हस्ताक्षर किया। समझौते के अनुसार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण पांच सालों के लिए हवाई अड्डों का संचालन और रखरखाव करेगा। पिछले वर्ष शिबपुर हवाई अड्डे के लिए इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अवसर पर हवाई अड्डा निदेशक देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण साझेदारी कार निकोबार और कैम्पबेल—बे हवाई अड्डों के संचालन में कारगर सिद्ध होगी।



सांसद बिष्णु पद रे ने अंतरद्वीपीय जलयान सेवा में कार्यरत जहाजरानी विभाग के नाविकों की वेतन से संबंधित मुद्दे पर मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित किया है। उनके नाम लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने वाले नाविकों के भाड़े में एक अप्रैल दो हजार बारह से संशोधन नहीं किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया है। भाड़े में वृद्धि न किए जाने की वजह से ऐसे नाविकों को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाईयां पेश आ रही हैं। वेतन भाड़े में संशोधन न होने के कारण कई रोस्टर नाविक बिना लाभ के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे भी संशोधित एरियर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सांसद ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत तौर पर मामलों को सुलझाने के लिए उचित निर्देश देने का आग्रह किया है।



भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल स्वराज द्वीप में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश महासचिव विवेक दधाकर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए किया गया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी गतिविधियों में शामिल करने का अनुरोध किया गया। साथ ही स्वराज द्वीप में एक पार्टी कार्यालय खोलने के बारे में भी चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य उपाध्यक्ष एम विनोद के अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।



विवेकानन्द ज़िला परिषद विद्यालय मध्योत्तर अंडमान की शासी निकाय की बैठक पिछले दिनों ज़िला परिषद के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। ज़िला परिषद अध्यक्ष ऐलिजाबेथ ने उपस्थिति का स्वागत किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष जून ने ज़िला परिषद की ओर से चलाई जा रही परियोजनाओं, खेल के सामग्रियों की खरीद के लिए उठाए जा रहे कदमों और ज़िले के तीन ज़िला परिषद विद्यालयों में प्रस्तावित मरम्मत और रखरखाव की जानकारी दी। विवेकानन्द केन्द्र ज़िला परिषद विद्यालय की नई समझौते पत्र के बारे में भी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। शुल्क में संशोधन के अलावा बैठक में कई अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में शारीरिक शिक्षा को अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल करने पर प्रस्ताव पारित किया गया। स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने और अग्निशमन उपकरणों को स्थापित करने पर भी चर्चा की गई, जिस पर कार्य प्रगति पर है।



समाज कल्याण विभाग के वन स्टॉप केन्द्र की ओर से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण पर ऑनलाइन जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। समाज कल्याण निदेशक डॉ. नितिन शाक्या ने कर्मशील महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कर्मियों में विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया। केस वर्कर मिनाल राजन ने वन स्टॉप केन्द्र योजना के उद्देश्य पर जानकारी दी। केन्द्रीय प्रशासक शांति मुरगेशन ने विशाखा दिशा-निर्देश के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सत्र के दौरान उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति का गठन और इसके कामकाज के बारे में भी जानकारी दी।

